[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

किसानों को और दूसरे लोगों को जो सहायता मिल रही है, उस चीज को नियमित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए यह लाया गया है। यह कोई नई चीज नहीं है बल्कि जो चीज पहिले से थी उसको बढ़ा रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the bill be passed".

The motion was adopted.

THE APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1973.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Sir, with your permission, I move:—

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1973-74, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, this Bill arises out of the Supplementary Demands for Grants of Rs. 123.04 crores voted by the Lok Sabha on 13th August, 1973 and expenditure of Rs. 10.01 crores 'charged' on the Consolidated Fund of India as detailed in the Supplementary Demands Statement laid before the House on 10th August, 1973. As full explanations have already been given in that Statement, I would confine myself to a few introductory remarks on some of the important items for which provisions have been sought.

This is the first batch of the Supplementary Demands for Grants during the current financial year and the amounts included therein represent the unavoidable minimum additional requirements which have arisen after the presentation of the Budget Of the additional requirements of Rs. 135.05 crores, Rs. 41.29 crores are on Revenue Account, Rs. 3.26 crores on Capital Account and Rs. 88.50 crores for disbursement of loans and advances.

Of the total amount of Rs. 135.05 crores, Rs. 50 crores are for increased assistance to States—Rs. 40 crores as grants-in-aid and Rs. 10 crores as loans—for providing relief and employment opportunities to the people affected by natural calamities.

The balance of the increase under Revenue is mainly on account of increased expenditure on the Third Asian International Trade Fair, 1972/National Industries Fair— Rs. 1.28 crores.

The increase of Rs. 3.26 crores on the Capital side is for making payment in the form of non-negotiable, non-interest bearing rupee securities to the International Bank for Reconstruction and Development for maintenance of value of India's 9% subscription funds. The payment has been necessitated by the revaluation of World Bank's holding of Indian currency with the central rate of Rs. 18.9677 equal to 1 pound sterling established following the Smithoonian Agreement relating to the currency realignment in December, 1971.

The balance of the additional requirements under Loan and Advances is for loan assistance to the Government of Bangla Desh for purchase of two ships from the Shipping Corporation of India (Rs. 4.50 crores) and for providing technical credits to the Governments of various countries, e.g. the U.S.S.R., certain East European countries, the Democratic Republic of Korea, the Sudan and Bangla Desh under the Trade Agreements entered into with those Governments (Rs. 74 crores).

A token provision of Rs. 1,000 has been sought for meeting expenditure of the Committee for standardisation of scales of pay, allowances and perquisites of the officers of the nationalised banks.

Two Appropriations on Revenue Account are for recurring advances obtained from the Contingency Fund of India to meet expenditure on a court decree and on award against the Government.

The additional requirements of Rs. 135.05 crores are likely to be set off to the extent of Rs. 45.76 crores by additional receipts, recoveries, etc. relating to those Supplementary Demands and the net

cash outgo would, thus, amount to Rs. 89.29 crores only.

Sir, I move.

The question was proposed.

4 P.M.

श्री टी० एन० सिंह (उत्तर प्रदेश) श्रीमन्, उपसभापति महोदय, मेरा इरादा बोलने का तो नहीं था, लेकिन जिस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था का इन्तजाम हो रहा है, इधर कुछ वर्षों से और जो उसमें ढिलाई आ रही है, इस वास्ते मैंने अपना फर्ज समझा की इस वक्त कम से कम गवर्नमेंट को और जनता को आगाह कर दूं कि यदि यह रवैया चलता रहा तो हमारी फाइनेन्सेज चौपट हो जायगी। 133 करोड से ऊपर की सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स 72-73 के बजट के विषय में मांगी जा रही है। उसमें खास तौर से बताया गया है एशिया ट्रेड फेयर का। एशिया फेयर '72 में हुआ था और जब बजट उसके संबंध में पेश किया गया था तो वह 3 करोड़ से कुछ अधिक था।

[THE VICE CHAIRMAN (SRI YOGENDRA SHARMA) in the Chair]

दिसम्बर में फेयर हुआ था। मार्च के महीने में दो बार सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स ली गई इसी के लिए। अब फिर जितनी ओरिजिनल ग्रान्ट थी उससे कहीं अधिक करीब 5 करोड़ से अधिक रुपया मागा जा रहा है। यह आर्थिक प्रबंध का सिलसिला अच्छा नहीं है। एशिया फेयर के लिए एक तो इतना अधिक खर्च होना ही नहीं चाहिए था। एशिया फेयर से लाभ उठाया किसने? जो उच्च वर्ग है उनको फायदा हुआ। निम्न वर्ग को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। दिल्ली के टेक्सी वालों ने पैसा बना लिया हो या बड़े लोगों ने यहां से फायदा उठा लिया हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को फायदा हुआ हो। इस व्हाइट एलिफेन्ट को पालने के लिए आज 8 करोड से अधिक रुपया जो खर्च किया जा रहा है, यह मेरी समझ में ठीक नहीं है। दुःख की बात यह है कि जितनी ओरिजिनल ग्रान्ट् थी उससे अधिक रुपया मागा जा रहा है, जब दो मर्तबा सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स इसी के लिए ली जा चुकी है। मेरा फाइनेन्स कमेटी से बहुत पुराना संबंध रहा है। मैं फाइनेंशियल प्रोप्राइटी और करेक्ट प्रोसीजर्स का बड़ा हामी हू। लोग मुझे इसके कारण कन्जरवेटिव भी कह सकते हैं और मैं उस इल्जाम को मानने के लिए भी तैयार हू। लेकिन आज जो मोनीटरी स्थिति है और इनफ्लेशनरी पोजीशन है, उसको देखते हुए अगर कोई चीज सबसे जरूरी है तो वह यह है कि हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचार रूप से, नियमित ढंग से चलाएं। यदि वह ऐसे चलाया जाय जैसे कि चलाया जा रहा है कि बजट प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन अंदाजा नहीं कि खर्चा कितना होगा। साल भर खर्च होता है और साल का आखिर आ जाता है, मार्च महीने में जो साल खत्म होता है उस वक्त भी अंदाजा नहीं है कि जितनी ओरिजिनल डिमांड थी उस से करीब दुगनी डिमाड हम को लेनी है। तीन करोड की जगह साढ़े पाच करोड़ लेना है। यह ठीक नहीं है। हमारा मुल्क आज एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। मै समझाता हूं कि यदि किसी विभाग का कोई कर्तव्य है और उसको अगर हमारा देश को बचाना है, उसके लिए उसे कोई काट्रीब्युशन करना है तो सब से अधिक काट्रीब्युशन इस दिशा में हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही कर सकती है। इंफ्लेशन को रोकना, बजट पर बजटरी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो

[श्री टी०एन० सिंह]

रनअवे इंफ्लेशन और भी रनअवे हो जायेगा तो इस वक्त मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक उदाहरण है आप की ढीली अर्थव्यवस्था का। और इसमें कोई दूसरी इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसको मैं आज कहूं, लेकिन यह उदाहरण बतलाता है कि किस ढंग से हवा हमारे आर्थिक विभागों में बह रही है। मैं आये दिन सुनता हूं कि हर तरफ हिलाई बर्ती जा रही है, बजट में रुपया दे दिया जाता है और उसका डिटेल्ड इस्टीमेट पहले से तैयार नहीं होता। नतीजा क्या होता है कि जितना इस्टीमेट है उससे ज्यादा खर्च होता है और जो खर्च होना चाहिए उतने समय में वह खर्च नहीं हो पाता है। तो यह बुराई 1949–50 से मैं बजट में देख रहा हूं। मेरा स्वतः का, निजी अनुभव है। मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में बरसों रह चुका हूं और मैंने हर साल के बजट को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया है और अधिकार के साथ मैं कह सकता हूं कि यह तरीका अगर खत्म नहीं होगा तो हमारे देश का फाइनेंस बर्बाद हो जायगा और यह नहीं किया जा रहा है पता नहीं मैं कितने कठोर शब्द इसके लिए इस्तेमाल करूं लेकिन मैं समझता हूं कि जरूरी है कि कोई आदमी इस सभा में, इस सदन में उठ कर कहे कि यह चीज अब बर्दाश्त नहीं की जायगी। इस वास्ते यह जरूरी है कि जो फाइनेंशियल प्रोप्राइटीज है, उन पर जोर दिया जाय। एक छोटा सा एशिया फेयर हुआ कोई इस्टीमेट नहीं रहा होगा। साढे तीन करोड का बाद इस्टीमेट हुआ और साढे आठ करोड़ खर्च हो जाय और मार्च के आखिर तक आते-आते आपको पता न रहे कि जब आप सप्लीमेंटरी ग्रांट मांगें और अब साढे पांच करोड़ की सप्लीमेंटरी ग्रांट मांग रहे हैं यह कहां तक उचित है। और मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में, राज्य सभा में या लोक सभा में कैसे यह चीज चल जाती है। इसकी तो जितनी निन्दा की जाय कम है और यह जरूरी है। मैंने यह भी देखा है कि एप्रोप्रिएशन से भी एक्सेस एक्सपेंडिचर हो जाते हैं और वह रेगुलराइज किये जाते हैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के जरिये, तो मैं चाहता हूं कि यह सब बातें हमारे यहां न आयें। हमें और बहुत सी कठिनाइयों का अभी सामना करना है और अगर हमने अपनी आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं किये तो हमारे सारे देश का आर्थिक ढांचा खतरे में है। इस वास्ते मैंने सिर्फ उदाहरण के रूप में यह बात कही। मेरा बोलने का कोई इरादा नहीं था और मैं बहुत दिनों से अपने देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं बोला हूं। आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि मैं कुछ कह दूं। लोग मुझे कहेंगे कि मैं कंजरवेटिव हूं। दकियानूसी बात कर रहा हूं, लेकिन आज कल के इंफ्लेशनरी जमाने में बजटरी कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। आप बड़े जोरों से डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं और मुझे याद है कि 1950 में पहले पहल जब फर्स्ट प्लान बन रहा था तो सोचा गया कि फर्स्ट प्लान का कुछ हिस्सा डेफिसिट फाइनेंस से भी फाइनेंस किया जाय। उसके लिए पूरा हैक्सेशन या लोन रेज न करें, उसे डेफिसिट का फाइनेंसिंग से पूरा किया जाय और बजट में डेलीबरेटली एक गेप छोड़ दिया जाय। मैंने उस वक्त बात चीत की थी। हमारे देशमुख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनसे बात की, मैंने कहा कि यह खतरे का रास्ता है। मैं समझता हूं कि हम लोगों को बहुत आर-थोडेक्स फाइनेंसिंग में नहीं होना चाहिए

और कुछ डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आप जानते हैं मैं एक कंजरवेटिव फाइनेंस मिनिस्टर हू, यह जो करेंसी है, इसके घोडे पर मै चढ़ा हू, उसका मै चलाना वाला हू, उसका संचालन करने वाला हूं, तो लगाम जब तक मेरे हाथ में है तब तक घोडा कैसा ही दौड़े उसको मैं रोक सकता हूं, इस वास्ते जो लगाम हमारे हाथ में रहे तो डेफिसिट फाइनेंसिंग से कोई चिन्ता नही है। आज लगाम हमारे हाथ से निकल चुकी है। यह बड़े खेद के साथ कहना पडता है---अपने देश के आर्थिक प्रबन्ध के बारे में कोई भी आदमी कहना नही चाहता; क्योंकि जो शब्द हम यहां कहते है वह बाहर भी जायगा, मुझको पूरा खयाल है, लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूं और समय आ गया है कि कहू कि चूंकि अब वह लगाम नही है, इसलिए घोड़े का दौड़ना किसी भी तरह से हो अपनी जान दे कर भी रोकना पड़े तो रोकना पड़ेगा, अगर घोडा दौड़ जाता है तो जान की बाजी लगा कर भी आदमी उसको रोकता है अगर उसको रोकना पड़े। तो यह बहुत जरूरी है, यह जो लाइटली आ जाता है पांच-पांच करोड़ की एक डिमांड, एक फेयर पर, क्या बात है? मैं आपको बता दू कि ब्लैक मनी जेनरेट होती है कांट्रेक्टर्स के जरिये और सबसे ज्यादा इसका बेनिफिशियरी, एशिया फेयर का, इससे लाभ उठाने वाला कौन था? कांट्रैक्टर्स। उन्होंने इससे फायदा उठाया और यह पैसा वहा गया। तो हम डेफिसिट फाइनेंसिंग ही नहीं कर रहे है ब्लैक मनी भी क्रिएट कर रहे है। इस वास्ते जरूरी है कि ऐसे मदों पर एतराज कम से कम हाउस में हो जाय---गवर्नमेंट ने तो खर्च कर दिया है उसको रोक नही सकते और लोअर हाउस से पास भी हो चुका है।

खैर, मैं आगे बढता हूं। मेरा एक सुझाव है फारेन ट्रेड के बारे मे। फारेन ट्रेड कई टर्म्स पर किया जाता है, क्रेडिट टर्म पर, पेमेंट इन अवर ओन करेंसी, रुपी पेमेंट बेसिस पर या एडजेस्टमेंट फ्राम टाइम टु टाइम कोई रिजर्व हो जैसे कि स्टर्लिंग रिजर्व रहा करता था, जिससे कि एडजेस्ट करते थे फ्राम टाइम टु टाइम इंटरनेशन बैंक के जरिये। ये सब तरीके थे। यह रुपी पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, जब हमने रशिया से माल मगाना शुरू किया तो उन्होने कहा कि यदि तुम फारेन करेंसी में रुपया नही दे सकते तो अपनी रुपे करेंसी में उतना रुपया मेरे नाम से अपने यहां बैंक में जमा कर दो। वह रुपया उनके नाम से जमा हो गया और फिर वह उस रुपये से यहा से चीजें खरीद कर अपना काम चलाते थे तो इस काम को जहा हम डेटर नही है; जहा हम क्रेडिटर है, वहां भी शुरू कर दिया है, यह रुपी पेमेंट सिस्टम सूडान से, बगला देश से, यहां सबसे भी शुरू हो गया है, मैं चाहता हू, मेरा बहुत विनम्र सुझाव है कि एक कमेटी इस पर बिठाई जाय जिसमे कि इसके एक्सपर्ट हों और वह इसको एग्जामिन करे, इसकी जांच-पडताल करे कि कौन सा सिस्टम हो। हर सिस्टम हो सकता है और होना भी चाहिए, मैं उसको रोकना नही चाहता, लेकिन जिस तरह से यह फंक्शन कर रहा है उससे मुझको संतोष नही है। कोई कह दे कि मैं उसकी डीटेल्स को यहा बता दू, तो यह बड़ा मुश्किल है। लेकिन हा, यदि फाइनेन्स मिनिस्ट्री के लोग इन्टरेस्टेड हों और मुझको इसका पूरा लिटरेचर मिले---अब तक जो ट्रान्जेक्शन्स वगैरह हुए उनकी डीटेल्स मिलें---तो मै जरूर अपने सुझाव पेश करना चाहूँगा। लेकिन इस वक्त

[श्री टी० एन० सिंह]

मेरे सिर्फ एक-दो छोटे से सुझाव हैं और वह यह कि गवर्नमेन्ट खुद अपने एक्सपर्ट्स के जरिए ये सारे सवालात, ये सारे मसले जो फारेन पेमेन्ट के, डिसबर्समेन्ट के है, ये एग्जामिन करे। हमने कई किस्म की चीजें की है, लाग क्रैडिट, साफ्ट क्रेडिट, रुपी पेमेन्ट, नेशनल डेवलपमेन्ट फण्ड के जारिए, फारेन क्रेडिट से, ये सब चीजें है, इन पर फिर से दूसरी निगाह डालने की जरूरत है, नहीं तो हम काफी कठिनाई में पड़ जाएंगे। यह काफी उलझे हुए मामले है।

दूसरा मेरा सुझाव था चूंकि फारेन ट्रेड के लिए इसमें एक सप्लीमेन्टरी ग्राण्ट मांगी गई है। (*Time bell rings*) अभी मैं खत्म करता हू, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारा रुपया डीवैल्यू हुआ, सन् 1966 के मई-जून मे। उस वक्त हमारे जो फारेन डेट्स थे, वे सब यकायक काफी बढ गए, डेढ़ गुने हो गए---55 परसेन्ट डेप्रीशिएट किया। अभी हमने अपने रुपी को डीवैल्यू नही किया इधर लेकिन डालर करेन्सी जो है वह फ्लोट किया और उसका एक रेट डिवैल्युएशन के शेप मे हुआ है। अब उसके कारण हम लोगो को पेमेन्ट जो वर्ल्ड बैंक मे करना पड़ता है वह करेन्ट रेट पर करना है। जो शार्टफाल रहेगा उसकी कमी की सीमा दूर कर देंगे। तो हम एक बोझा करीब 3 करोड़ से ऊपर दे रहे है--टु मेक गुड दैट करेन्ट रेट आफ द रुपी-डालर वैल्यु। तो आखिर जो रुपया डीवैल्यु किया तो भी हम लोगो को पे करना पड़ा और अब जो हमारी कम्पैरिजन में डालर डेप्रीशिएट किया तो भी वह हमें देना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है? कुछ हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, आई० बी० आर० डी० मे हमारे रिलेशन्स ऐसे हो गए है कि चोट पहुचती है और वर्ल्ड बैंक जो है यह हमारे फाइनेन्सेज मे हल्के-हल्के काफी असर डालता जा रहा है। मैं आगाह करता हू कि वर्ल्ड बैंक का जोर बढ़ने के मानी होते है कि अमरीका का जोर बढ़ना। मैं जब प्लानिंग कमीशन का मेम्बर था तो मेरे पास वर्ल्ड बैंक के लोग आए थे, उनको बड़ी ख्वाहिश हुई कि हमारी रेलवेज ने 250 करोड़ रु० और खर्च किया और उन्होंने उसके लिए कहा कि हम क्रेडिट देंगे अलग से और वह रुपया खर्च किया गया और रेलवे वालों ने कहा और बडे-बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा कि उसके हो जाने के बाद 245 मिलियन टन कैरीइंग कैपेसिटी, ट्रान्सपोर्ट कैपेसिटी रेलवे की हो जाएगी। आज अथी तक हम 245 मिलियन टन वाले टार्गेट पर नही पहुंचे है और हमको रेलवे पर खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो हम कोर्स हो जाते है वर्ल्ड बैंक और बड़े एक्सपर्ट्स के नाम से---एण्ड वी रश इन्टू एकसपेंडीचर--लेकिन हम रेजिस्ट करते थे, मगर हमारी एफ नही चलती थी। तो मेरा यह ख्याल है कि हमको वर्ल्ड बैंक से रिलेशन्स स्थापित करने वक्त बडा सतर्क रहना चाहिये।

आखिर में अगर आप आज्ञा दें तो शब्द स्टेटों को जो सहायता दी जा रही है उसके सम्बन्ध मे कह देना चाहता हूं। आजकल स्टेटों को अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए सहायता दी जा रही है। आज भी 100 करोड़ और 50 करोड़ रुपया इस तरह के क्षेत्रों को राहत कार्य के लिए दिये गये है। यह उचित बात है। लेकिन मेरा यह खयाल है कि जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर आप कम दे रहे है। आप इस तरह से कितनी बार यहा पर सप्लीमेंटरी ग्रान्टस लायेंगे? 100 करोड़ रुपया तो बजट मे था, मै चाहता हू कि आप हमको

कांट्रेडिक्ट करेंगी। महाराष्ट्र और गुजरात को 93 करोड रुपया इस कार्य के लिए दिया गया है।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : वहा पर कहत पड़ा हुआ था।

श्री टी० एन० सिंह. लेकिन मैं यह कहना चाहता हू कि महाराष्ट्र और गुजरात की आबादी करीब 8–9 करोड़ के होगी, इससे ज्यादा नही है। भारत-वर्ष के जो दूसरी प्रदेश है वे भी उतने ही प्यारे है जितने महाराष्ट्र और गुजरात के है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी और सेन्ट्रल हिस्सा है, सारा बिहार है, उसकी आबादी 7–8 करोड़ के होगी, इससे कम नही है। आप किस तरह से उम्मीद कर सकते है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए जहां पर सूखा पडा है, 50 करोड़ से काम चल जायेगा और वहां की जो समस्याए है वे हल हो जायेंगी? मैं यह नही कहता कि आपने गुजरात और महाराष्ट्र को 93 करोड़ रुपया क्यों दिया या आपने गलत कार्य किया। (*Interruption*) चौधरी साहब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनें। मैं तो यह कह रहा था कि आपको फिर सप्लीमेटरी ग्राट्स के लिए आना पड़ेगा।

अगर आप आज्ञा दे तो मैं अपने तजुर्बे की वजह से एक पुरानी बात कह देना चाहता हूं। प्लानिंग कमीशन मे इस तरह की रिकमेन्डेशन हो चुकी है कि जहा पर ड्राट पड़ जाय, जहा पर स्केयरसिटी हो जाये, वहा पर किस तरह से खर्च किया जाय। इस तरह की जगहों के लिए प्लानिंग कमिशन ने पहिले से ही योजना बनाई है कि इस तरह के क्षेत्रों मे कम्युनिटी एसेट्स के लिए ज्यादा खर्चा किया जाय। अगर पहले से ही बांध बन्ध जायेगा तो पानी आ जायेगा। किसान तो खेती को ठीक करके ही पानी का इस्तेमाल करता है और इस तरह के कार्य से 6 महीने के अन्दर पानी मिल जायेगा और इस तरह से हमारी उपज भी बढ़ जायेगी। तो हम लोगो ने इस तरह के सुझाव दिये हैं और ये सात, आठ वर्ष पुराने सुझाव है। हमने इस तरह का सुझाव दिया था कि पहिले से ही इस तरह की स्कीमें बना ली जानी चाहिए कि जहा कही भी इस तरह की स्थिति आये, वहा पर कम्युनिटी एसेट्स के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह की स्कीमे यू० पी०, हरियाणा, पंजाब और सब प्रान्तों के लिए बना लेनी चाहिए। जब इस तरह की स्थिति आये तो इन स्कीमों पर अमल किया जाना चाहिए। आजकल होता क्या है कि स्कीमों को आने मे ही तीन, चार महीने लग जाते है और फिर काम शुरू करने मे समय लग जाता है। अगर इस बीच भुखमरी हो गई तो फिर किस तरह से वहा के लोग टैस्टवर्क मे काम कर सकते है। यह बात ठीक नही है। मैं इतना सुझाव दे देना चाहता हू। मुझे और ज्यादा कहना नही है, लेकिन मैंने सोचा कि 133 करोड़ रुपये की बात है, अगर मै हाउस का इस सम्बन्ध मे कुछ समय ले लूगा, तो कोई अनुचित नही होगा। आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हू।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार जब पहले बजट लाती है तो उस समय घाटा कम दिखलाती है और इस तरह से धीरे-धीरे घाटा बढ़ता ही चला जाता है। सरकार की मांग भी पुन: बढती ही चली जाती है, इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हू कि आज देश में जो भयंकर महंगाई है, अनाज नही

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

मिल रहा है, चारों तरफ के ग्रोस का वातावरण उपस्थिति होता जा रहा है, मैं इन चीजों का मुख्य कारण आपका बजट मानता हू और क्या आपकी बजट की गड़बड़ी इन सब चीजों का कारण नहीं है?

श्रीमन्, घाटे का बजट, नोट की अधिक छपाई के कारण पहिले से ही दिल्ली मे छोटी चेन्ज का मिलना अराम्भव हो गया है। उसके बाद लगा कि छोटे-छोटे नोट भी शायद अप्राप्य हो रहे है। यह एक छोटा सा उदाहरण था जो यह बताता है कि इस देश की आर्थिक स्थिति भयंकर ढ़ंग से डांवाडोल हो रही है। आज कोई भी ऐसा विभाग नही है जो धीरे-धीरे आन्दोलन का रूप न पकड़ रहा हो। पहले सुना जाता था कि मज़दूर आन्दोलन करते हैं, इसलिए कि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हे पैसा नही मिलता---आज भी नही मिलते है---इसलिए उन्हे संघर्ष करना पड़ता था, वे भूखे थे, नगे थे, लेकिन आज इजीनियर भी हड़ताल करते है, जिनको हम अधिकारी कहते है, वे भी हड़ताल करते है, उनका भी पेट नही भर रहा है। आप यह स्वीकार करेंगे और आपने यह स्वीकार किया भी है कि आपके रुपए की कीमत बहुत घट गई है, उसकी परचैजिंग कैपेसिटी बहुत घटी है और जो वेतन उसको मिलता है उससे वह जिन जीवनोपयोगी चीजों को खरीदना चाहता है वह खरीद नही सकता है। तो एक तरफ आपका घाटे का बजट, नोटों की छपाई और दूसरी तरफ पेरेलल ब्लैक मनी---इन दोनों के चक्कर मे भारतीय समाज पिस रहा है और आप मोहक शब्दों से जनता के आसू पोछना चाहते है। कैसे आंसू पोछे जाएंगे?

आप तमाशा खड़ा करते है एशिया फेयर का। जो खर्च निश्चय करते है दुगुने से ज्यादा बढ जाता है। मै माननीय मत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि इस तमाशे से देश को क्या-क्या लाभ मिले?

श्री रणबीर सिंह. एशिया मेले को तमाशा कहते हो?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: मेला जो तमाशा बन जाता है कभी कभी। इसीलिए मैंने जानबूझकर उसको तमाशा कहा।

श्री रणबीर सिंह: तमाशा नही, देश की इज्जत बढाने वाला था।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: अगर आपकी बातों मे महंगाई मे, बेकारी से, भ्रष्टाचार से, देश की इज्जत बढ़ती हो तो कुछ नही कहा जा सकता।

श्री रणबीर सिंह. उसके लिए तो आप जिम्मेदार है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: श्रीमन्, आज हमारे एक सहयोगी कोट कर रहे थे कि भ्रष्टाचार का नमूना विदेश के पत्रों में निकलता है कि भ्रष्टाचार हेड मे फुट बराबर भरा हुआ है। पहले भ्रष्टाचार की बात हम कहते थे, अब जो दूर बैठे हुए है वे भी आपकी प्रतिष्ठा को आंक रहे है। देश की प्रतिष्ठा जब बढ़ती है तब चारो ओर बढ़ती है, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा सब क्षेत्रों में दिखाई देती है। जापान में भी मेला लगा था। उसका भी दृश्य देखे और आपका भी मेला लगा था। जापान ने मेला लगा कर पहले भी दिखा दिया था और बाद में भी कि दुनिया के मार्केट पर उसका कितना वर्चस्व है। वह भी

गुलाम हो गया था, कुछ ही पहले आजाद हुआ है। उसकी प्रगति देख लें लोहे के उत्पादन में, व्यापार में, जो उस पर राज्य करता था आज उसको भी पीछे छोड़ कर आगे जा रहा है। एक छोटा देश जर्मनी भी गुलाम हुआ था, वह कई टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन अब गुलाम बनाने वालों को पैसा देने की स्थिति में है। आज वहा कामों का अम्बार है। हमारे यहा 25–26 वर्ष की आजादी में क्या मिला? इज्जत की बात करते हैं। हमने पहले कहा था कि हमारा देश अन्न के मामले मे स्वावलम्बी हो गया, हम कटोरी लेकर भिक्षा देहि, भिक्षा देहि की बात नही करेंगे, लेकिन हमें फिर मांगना पड़ा। क्या यह इज्जत है?

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता). सूखा पड गया तो उस में हमारा क्या वश है?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: इतना बड़ा देश जिस का नाम अन्नपूर्ण था, उसकी यह हालत है। अगर बारिश या सूख के कारण यह होता तो हम आपके साथ होते। लेकिन कारण तो यह है कि जितने कुएं कागज पर खोदे गये उतने खेतों मे खुदे नही और जो कुए खेतो मे भी खोदे गये उनका पानी खेतों तक पहुच जाता तो शायद यह अकाल न पडता। अगर अकाल की बात होती तो पंजाब में और हरियाणा में भी अकाल पड़ता। वहां यह बताया गया कि चूंकि वहा स्कीम्स वर्क आउट हुई हैं इसलिए वहां अकाल नहीं पडा। अकाल वही पड़ा है कि जहा सचमुच में कृषि को ढंग से समझा नहीं गया और समूचे देश मे 12, 14 स्टेट्स में अकाल होने का कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार की योजना ठीक नही थी। उस को कृषि-उन्मुख योजना होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। इसी लिए मैं नहीं चाहता था कि इस बात को यहा उठाया जाय। आपकी इज्जत बढ़ी है देश में और विदेश मे और इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हू। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता था कि आज इस देश के लोगों के पेट जल रहे है और आज जरूरत इस बात की है कि आप अच्छे मकान और उनको अच्छी व्यवस्था न भी दें, बल्कि जरूरत इस बात की भी है कि आप उनके पेटों के लिए खाने को ही दें। आज इस देश में हाहाकार इसी लिए मचा हुआ है और इस देश की आर्थिक स्थिति झंझावात में पड़ती चली जा रही है। आपकी इज्जत का पता तो इसी से चलता है कि आपके रुपये की कीमत क्या है? आपके रुपये की कीमत केवल रूस के व्यापार मे कम है जो लाचारी मे पड कर उस ने किया था। लोग बेबस थे। रूस के ऊपर निर्भर थे। रूस जैसा कहता है वैसा आपको करना पड़ता है। उस रुपये का दुरुपयोग रूस करता था और पी० एल० 480 का दुरुपयोग अमरीका करता था। छोटे-छोटे देशों की मुद्रा की इज्जत है, लेकिन आप उनके भी नीचे चले गये है। क्या आप की स्थिति इतनी बेकाबू हो गयी है कि आप को उनके नीचे जाने के लिए मजदूर होना पडा? इसी लिए मैने कहा था कि आप तमाशा न करें।

आज श्रीमन्, देश में भूख से चिल्लाने पर लाठी और गोली मिलती

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

है। अभी भोपाल में प्रदर्शन हुआ और एक प्रदर्शन में गोली चला कर दस आदमियों को भून दिया गया। तो एक तरफ तो मेठी जी की सरकार है जो विद्यार्थियों पर गोली चलाती है, उसमें विद्यार्थी भी थे और दूसरी तरफ हमारे हरियाणा में हमारे बंशीलाल जी की सरकार है जो कि विरोधी दलों की मीटिंग भी नहीं होने देती। और अगर उनके सामने प्रदर्शन करने महिलायें जाती हैं तो उन पर भी लाठियों से प्रहार होता है।

श्री रणबीर सिंह हरियाणा में कोई सुनने नहीं जाता आपको।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: सुनने नहीं जाते क्योंकि वे बेवकूफ हैं। इसी लिए आप सोचते हैं कि पुलिस को भेज दें और उनका कुछ स्वागत पुलिस के द्वारा करें। बड़ा हल्ला मचा कि हरियाणा में गांव-गांव में बिजली लग गयी। मुझे भी शौक चर्राया कि देखूं कि वहां क्या है तो पता लगा कि बिजली तो है, बिजली के बल्ब लटके हुए हैं, पंखिंग सेट लगे हुए हैं, लेकिन वह चलते नहीं हैं। अब ये बल्ब जलते नहीं हैं तो उसका कारण क्या है?

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) बिजली लगाने में खर्च दुगना और तिगुना किया गया है, जितना कि होना चाहिए उससे।

श्री रणबीर सिंह: फिर भी आप के प्रदेश से वह 25, 30 परसेंट सस्ता है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव हरियाणा को जो वर्चस्व मिला हुआ है, चौधरी बंशीलाल जी को जो वर्चस्व मिला हुआ है वह इसलिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है और उस उपकार के आगे हमारी प्रधान मंत्री जी दबी हुई हैं और उसके कारण ही हमारी सारी सरकार दबी हुई है। (*Interruptions*) मैं बार-बार मारुती लिमिटेड का नाम नहीं घसीटना चाहता था, लेकिन अगर हमारे बड़े भाई ने टोका ही है तो मुझे कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। . . .

श्री रणबीर सिंह: यहां मारुती कहां है?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: जिस ने डिफेंस की परवाह नहीं की, किसी कानून की परवाह नहीं की, आज वह कारखाना चौधरी बंसी लाल के लिए एक कवच साबित हो रहा है (*Interruptions*) उनकी महिलाओं पर लाठियां चलती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कहा गया था कि अगर पार्लियामेंट के सदस्य लिख कर दें तो जांच होगी, राष्ट्रपति जांच करायेंगे। लेकिन कितने ही पार्लियामेंट के सदस्यों ने लिख कर इनके खिलाफ दिया तो क्या कोई जांच हुई। मुझे अफसोस इतना ही है कि अगर चौधरी बंशीलाल पर जांच करनी थी तो वह हो जाती अगर उनके साथ से मारुति को हटा लिया जाता, लेकिन चूंकि मारुति साथ था, इसलिये जांच नहीं हो सकी, अगर मारुती का कवच इसी तरह चलता रहा तो प्रदेश का क्या होगा?

श्री रणबीर सिंह: तरक्की होगी।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: इन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेश वाले हमारी तरह

काम करें, लेकिन प्रदेशों को काम करने लायक रहने दिया जाय तब तो काम करें। बिहार में मंत्रिमंडल का परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन इसलिये होता है कि दूसरे प्रदेश का चुनाव होना है, अगर बहुमत किसी अच्छे नेता को चाहता हो कि उसका वह मुख्य मंत्री बने तो और बात है, लेकिन वहां पर यह देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीतना है, उनको पता लगा कि मुसलमान बन्धु उनके साथ नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रभाव अपना ठीक करने के लिये बिहार के सिर पर ऐसे श्रीमान गफ्फूर साहब को लाद दिया गया और वह कब रफ्फू हो जायेंगे इसका भी पता नही, ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव तक टिके रहें, तो टिके रहें, मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा टिकेंगे । गफ्फूर साहब का इतिहास क्या है? गफ्फूर साहब के इतिहास से कुछ करना नहीं है, लेकिन गफ्फूर साहब का इतिहास क्या है ? यह सभी जानते हैं और गफ्फूर साहब का इतिहास आपके कांग्रेसी लेजिस्लेचर भी जानते हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस सब का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री योगेन्द्र शर्मा) : राज्य के मुख्य मंत्री की बात छोड़ दीजिये।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : वह टोकते जा रहे है, इसलिये इतनी बात कहनी पड़ती है। उनको आपने रोका नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री योगेन्द्र शर्मा) : राज्य के मुख्य मंत्रियों की बात यहां पर करना ठीक नहीं है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इसमें तो राज्य की बात कौन कहे जिला और ग्राम पंचायत की बात, भी कही जाय तो शायद वह भी आ जाय, लेकिन चूंकि वह टोकते जा रहे हैं, उनको आप रोकने वाले नहीं हैं, वह चौधरी बंशीलाल से बहादुर आदमी हैं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री योगेन्द्र शर्मा) : अच्छा, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं चन्द मिनटों में समाप्त करता हूं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि आप सप्लीमेंटरी डिमांड ले आई है, लेकिन जो पिछड़े हुये प्रदेश है, उन प्रदेशों का भी कुछ हिसाब किया गया है क्या? पिछड़े हुये प्रदेश बराबर पिछड़ते जा रहे है। अभी कृषिक पुनर्वित्त निगम की बात थी तो उसमें भी यही बात आती है कि जो प्रगतिशील स्टेट हैं वह सारी जो आर्थिक सहायता है उसको निगल जाते है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसी प्रकार जो अच्छे स्टेट हैं वह सब ले जाते हैं और बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं वह अपनी फाइनेंशियल स्थिति को ठीक नही कर पाते है। तो मैं इस संदर्भ में एक बात यह अवश्य अपनी मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या पिछड़े प्रदेशों का भी कोई हिसाब किया है। उनके यहां उद्योग, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सारी चीजें पिछडती हैं और जो उन्हें देश में औरों के पैरेलल आना चाहिये, वह नहीं आ पाते है। तो मैं इस बारे मे जानना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री योगेन्द्र शर्मा) : आप समाप्त कीजिये। समय हो गया।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं खत्म किये देता हूँ। मुझको एक बात

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

और पूछनी थी। आपकी योजना में कृषि का स्थान ठीक से रहता नहीं है। और जो कुछ है उसमें भी सूद की दर आप किसानों के लिए बढ़ाते जाते हैं। तो वह सूद की दर अगर बढ़ा भी दिया है, 2 प्रतिशत, तो उसको कम करने की बात क्या आप कर सकेंगे? और अगर वह कम नहीं करेंगे तो जो किसान के करने की बात होगी पैदावार बढ़ाने की, वह चीज़ भी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आप इन्डस्ट्री के उत्पादन में मदद करते हैं, उसी प्रकार आप किसानों के लिये भी करें।

श्री महावीर त्यागी: किसानो की बात मत करें। किसानों पर जुल्म होने दो, उसका जवाब अगले इलेक्शन मे मिल जाएगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: इलेक्शन में जवाब मिले न मिले, लेकिन जब तक उनके प्रतिनिधियों के रूप में हम मौजूद है हमारा काम है ...

उपसभाध्यक्ष (श्री योगेन्द्र शर्मा): अब समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: इसीलिए हमने आपके सामने बात रखी है। मैं समझता हूं, मत्री महोदय इसका जवाब देंगे।

श्री रणबीर सिंह: उपसभाध्यक्ष जी, एप्रोप्रिएशन के तीसरे विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यहां मेरे से पूर्ववक्ता ने ज़िक्र किया विदेशी ट्रेड मेले का -- एशिया 1972 का ज़िक्र किया — और उनका खयाल है कि इससे हमारे देश की शोभा नही बढ़ी। उन्होंने ज़िक्र किया जापान का कि जापान के ऊपर जो हाकिम थे, आज उनका कन्ट्री जापान पर निर्भर है, जापान का व्यापार उनके ऊपर छाया है। उन्होंने जिक्र किया जर्मनी का। जर्मनी को हराने वाला और दबाने वाला आज जर्मनी की तरफ देखते हैं, आस लगाए बैठे है। मुझे दुःख है कि जिस देश के अंदर पैदा हुए हैं मेरे पूर्ववक्ता सदस्य, वे अपने देश की शोभा को घटाना चाहते हैं। वे इस बात को भूल गए कि हिन्दुस्तान जिस वक्त आज़ाद हुआ और पहले जब आज़ाद था। जिस देश से कपड़ा जाता था विलायत में वहां के कारीगरों के हाथ काटे और मैनचेस्टर का कपड़ा हिन्दुस्तान में बिकने लगा, इस देश की यहां तक गिरावट आई कि सुई भी जापान से आने लगी। क्या मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि आज हमारे देश ने कहां तक तरक्की की है? उल्टे बांस बरेली को गए हैं, लेकिन उनको दिखायी नहीं देता है कि आज हिन्दुस्तान की बनी हुई मशीनें विलायत में जा रही है...

SHRI NAWAL KISHORE (Utter Pradesh): Mr. Ranbir Singh, this is not a public meeting. You are speaking in the Rajya Sabha.

श्री रणबीर सिंह: इस बात को आप मुझको नहीं बताइएगा। अगर आप बताना चाहेंगे तो मैं फिर आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। आज हमारे देश के अंदर विदेश का व्यापार कहा तक बढ़ा है। यहा की बनी मशीनें विलायत में बिकती है...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: कर्जा कितना बढ़ा है, यह भी बताइए।

श्री रणबीर सिंह: जहा हिन्दुस्तान मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े पर आश्रित था, वहां आज हिन्दुस्तान का बना हुआ कपड़ा विलायत में बिकता है। मेरे दोस्त ने पंजाब का, हरियाणा का जिक्र

किया। उनके लिए मारुति भूत बन गया है। जो हिन्दुस्तान के गरीबों को कार देने के लिए कारखाना लगाया है उनके लिए भूत बन कर रह गया है और यह भय लग रहा है कि वह कारख़ाना तो तरक्की कर रहा है। यह सब आपकी मेहरबानी से नहीं हो रहा है कि इन्जीनियर आंदोलन कर रहे हैं, आज देश का हर अंग जो है वह देश की मदद नहीं कर रहा है। कौन आंदोलन करा रहा है? इसके पीछे तो आपका ही हाथ है, आप उकसा रहे हैं। आप मुझे बताइए आप तो बड़े किसानों के हमदर्द हैं, जिस देश के अंदर आम आदमी की आमदनी 400–500 रु० सलाना हो, उसके इन्जीनियर भी 500 रु० महीना तनख्वाह लें और वह इन्जीनियर स्ट्राइक करें तो आप उसका समर्थन करें? तो आप किस को समर्थन दे रहे है, जब देश के लोग नहीं समर्थन देना चाहते हैं उनको। नवल किशोर जी, मुझे क्या पता है कि इस वक्त आप को दिमागी बुखार हो गया है, आपको यह बात पसन्द नहीं। सब जानते हैं, कड़वी कुनैन बुखार का इलाज करती है, लेकिन कुनैन को खाने से आदमी फिफकता है। यह आपके लिए कुनैन है, आपके दिमाग़ के बुख़ार को तोड़ने के लिए दवा है। अगर आप आसानी से नहीं खाएंगे तो आपका हाथ पकड़ कर भी हमको खिलाना पड़ेगा; क्योंकि हमको तो आपके बुखार को तोडना है। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हू कि श्री टी० एन० सिंह जी का जो सुझाव है वह सही सुझाव है। त्यागी जी का ख़याल है कि महाराष्ट्र को इसलिए ज्यादा रुपया दिया गया है; क्योंकि वित्त मंत्री जी, श्री चव्हाण साहब महाराष्ट्र से आते है। त्यागी जी की इतनी उम्र हो गई है, इतने साल आप विधान सभा में रहे, कांस्टीट्युएन्ट असेम्बली में रहे, लोक सभा में रहे, मंत्री रहे और आज आप इस स्तर पर आ गये हैं। उत्तर प्रदेश के लिए पैसा कौन नहीं देना चाहता है, आप मांगिये और हम सब उसका समर्थन करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अगर तंगी है तो आप उसके लिए पैसा मांगिये और हम सब लोग उसका समर्थन करेंगे।

मैं तो इससे भी आगे जाता हूं कि जिस प्रान्त में भी जो अकालग्रस्त इलाके रहते हैं, उनके लिए अभी से योजना बनाइये ताकि वहां पर अकाल ही न रहे। इस काम के लिए पैसा दिया जाये और इस बात का इन्तजार क्यों किया जाय कि जब वहा पर अकाल पड़ेगा तब ही वहां पर योजना कार्यान्वित होगी।

श्री महावीर त्यागी: मैं आपकी इस राय को बिलकुल सपोर्ट करता हूं।

श्री रणबीर सिंह: मैं जानता हूं कि आप इस बात की सराहना करेंगे, लेकिन आपको तो महाराष्ट्र के नाम पर बुखार चढ़ आया है। आप भी तो वित्त मंत्री रह चुके हैं।

श्री महावीर त्यागी: आप मुझे कुनैन दे दीजिये।

(Interruption)

श्री रणबीर सिंह: रोहतगी जी भी तो उत्तर प्रदेश से आई हैं, वहां से चुनकर आई है।

श्री महावीर त्यागी: उनको चव्हाण साहब ने गोद ले लिया है।

(Interruption)

श्री रणबीर सिंह: श्री नवल किशोर जी से तो मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि उनको मेरी बात पसन्द नहीं है और

[श्री रणबीर सिंह]

यही कारण है कि वे बीच बीच में बोलने के लिए उठ जाते हैं। सच्चाई को समझने सुनने में जरा मुश्किल होती है।

तो उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि श्री टी० एन० सिंह जी ने एक जमाने की याद दिलाई जब वे योजना कमिशन के सदस्य थे। उस वक्त उन्होंने सुझाव दिया था ऐसे इलाकों के लिए स्कीम तैयार रहे, जहां पर अकाल होने का खतरा बना रहता है।

(Interruption)

मुझे तो कोई प्रलोभन नहीं है। मैं तो मंत्री रह चुका हूं, मगर आप अभी तक नही बने हैं और इसीलिए परेशान हैं। आपको वहां रहते हुए भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि आप मंत्री बन पायेंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, मेरे पूर्व वक्ता यादव साहब कह रहे थे कि हरियाणा और पजाब के अन्दर कहत का असर नही हुआ। क्या वे इस बात को भूल गये कि हरियाणा ने पिछले साल 8 लाख 90 हजार टन गेहूं दिया था। हरियाणा का इरादा इस साल 13 लाख टन गेहूं देने का था, लेकिन अकाल की वजह से, पानी की कमी की वजह से, नहरों में पानी कम आने की वजह से, खाद न मिलने की वजह से, हम इस टार्गेट को पूरा नही कर सके। इसी तरह से पंजाब, जिसने पहिले 32 लाख टन गेहूं दिया था और इस साल 34 लाख टन गेहूं देने का वादा किया था, वह केवल 26 लाख टन गेहूं ही दे सका। एक तो कहत का असर हुआ था, लेकिन मै इस बात को मानता हू कि जहा पर काम होगा वहां पर कहत का असर कम होगा। हमारे प्रदेश के अन्दर अगर काम नही होता तो जो हमारा सूखा इलाका है, वहां पर अकाल जैसी स्थिति बनी रहती और बुरा हाल हो जाता। चूंकि वहां पर काम था, पानी वहा पर पहुंचाया जा सकता था, इसलिए लोगों को काम चलाने लायक स्थिति वहां पर बनी रही। तो इसी तरह से दूसरे प्रदेशों में जहां तरक्की हो सकती है, वहां वित्त मंत्रालय ज्यादा से ज्यादा सहायता दे। मैं इस बात के हक में हूं कि किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय ताकि विदेशों से जो हम व्यापार करते है, उसमें ऐसी स्थिति हो जाय कि हम ज्यादा पैदा करके भेज सकें। आज हमारे लिए यह शोभा की बात नहीं है कि हम अपने देश से विदेशी मुद्रा कमाने के लिए कच्चा लोहा बेचते हैं। यह देश की तरक्की की निशानी नहीं है। हम रुपया कमाने के लिए मजबूर हैं ताकि देश की तरक्की हो। तरक्की हो कैसे? आन्दोलन से नहीं होगी। यादव भाई जिक्र करते हैं जापान का। जापान के अन्दर कोई आन्दोलन नही करता। वहां होड़ स्ट्राइक्स की नही है, वहां होड़ काम करने की है, वहां स्ट्राइक्स को कोई जानता नही। जर्मनी की बात आप करते है। जर्मनी के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर जितने मेन-अवर खोए जाते है, उनका मुकाबला करें तो आपको पता चलेगा। हमारे देश के विरोधी दलों ने इरादा किया कि इस देश की शोभा नहीं बढ़ने देनी, देश का नाम नही ऊंचा होने देना, उसमें उनको ही घाटा हुआ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: आप गलत कह रहे है। जिस समय देश पर आफत आई देश के विरोधी दलों ने एक होकर मुकाबला करके बता दिया कि देश की इज्जत और आबरू कैसे बचाई जाती है। आज आप विरोधी दलों

मे सभी क्षेत्रों में खुले दिल से सहयोग की बात करते तो यह मंहगाई, बेकारी, अकाल न होता। यह आपकी सरकार पर लानत है कि उसने इस तरह का सहयोग नहीं लिया और फिर आप गलत इल्जाम लगाते हैं।

श्री रणवीर सिंह: आप जानते है कि आज देश की क्या स्थिति है। हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति ने और हमारी प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को देश को इशारा किया, देश से अपील की और वह यह थी कि आन्दोलन के बजाय काम की तरफ चले। प्रधान मंत्री जी ने माना कि हमारे विधान के अन्दर हक के लिए स्ट्राइक कानूनी चीज है, लेकिन आज हमारे देश की हालत ऐसी है कि हमें उसकी तरफ जाना छोड़ देना चाहिए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: स्ट्राइक आपके मंत्री करवाते हैं। रेलवे में स्ट्राइक किसने करवाई?

श्री रणवीर सिंह: यादव जी मेरा समय लेते है, लेकिन रेल मंत्री जी उनके सिर पर भूत बन गए है। कहीं उनको संजय गांधी दिखाई देते है...

श्री नवल किशोर: श्रीमन्, तीन भूत हो गए है, हरियाणा, महाराष्ट्र और रेलवे मंत्री।

श्री रणवीर सिंह: हरियाणा की तरक्की को देखकर अपने प्रदेशों मे कैसे तरक्की हो सकती है उसको सीखो और अपने प्रदेश मे वह करवाने की कोशिश करो। पिछले बिल पर बोलते हुए कुछ सदस्यों ने बताया कि वहा की सरकारें पैसा नही मांगती। तो अगर पैसा नही मांगती तो रोशनी जी कैसे दें दें? दूसरे पैसा मिले और खर्च न हो तो क्या किया जाय? इस प्रदेश मे सरकार के लिए जो हमेशा कुश्तमकुश्ती रहती है इसे बन्द करें तब काम चल सकता है।

बिजली की तारों की बात करते हैं। आपके यहां तो बिजली के तार भी नहीं। आप क्या देखने गए थे हरियाणा? यही देखा होगा कि बिजली की तारों में कितनी शक्ति होती है। जरा हाथ लगाते तो पता चल जाता कि बिजली की तारों में कितनी शक्ति होती है। हाथ लगाया नहीं, कार में बैठकर गए, कार से वापस आ गए। तो हाथ लगा कर पता करते कि बिजली की तारों में कितनी शक्ति है।

श्री नवल किशोर: जैसे चौधरी लोग बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे हैं।

श्री रणवीर सिंह: नवल किशोर जी, मैं व्यापारी जैसी बात कैसे कह सकता हूं, मै काश्तकार हूं और काश्तकार जैसी बात करूंगा, आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूं। आप का मुकाबला मैं करना नहीं चाहता। उपसभापति जी, अभी जिक्र हुआ रूस की सहायता का। मै मानता हूं कि इस देश की तरक्की में रूस ने जो हम को इमदाद दी है, देश को बनाने में, हर सदस्य को उस की सराहना करनी चाहिए। यह बात दुरुस्त है कि अमरीका ने भी हम को अनाज दिया और अनाज बहुत जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन वह तो शाम को खाया सवेरा बार हुआ। उस से तरक्की नही होती। (*Interruption*) मै मानता हूं कि हमारे देश के लिए उस ने अफीम का काम किया। हमारे त्यागी जी जब वित्त मंत्री थे, उस वक्त उन को ख्याल नही आया, क्योंकि उस वक्त वहां पी० एल० 480 से पैसा मिल जाता था, चिट्ठी लिखी और अनाज आ जाता था। उस वक्त हमारे दोस्त श्री टी० एन० सिंह

(श्री रणबीर सिंह)

जी योजना कमीशन में थे उस वक्त उन को इस बात का ख्याल नही आया कि हम जो दस्तखत कर के अनाज ले रहे हैं उस से देश की तरक्की नही हो सकती। देश की तरक्की तभी होगी जब देश मे ऐसे कार्य किये जाय जिन से कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, तरक्की हो। श्री टी० एन० सिंह मुख्य मंत्री थे। याद होगा उन को कि मैं ने एक पत्र उन को लिखा था कि आप अपने प्रदेश की सरकार की तरफ से जो नेशनलाइज्ड बैंक है उन को किसानों के लिए गारंटी दें ताकि वह किसानों को कर्ज देना शुरु करें और मुझे खुशी है कि उन का जवाब बहुत अच्छा था . . .

श्री टी० एन० सिंह : मैं चौधरी साहब को बता सकता हूं कि जितने नेशनलाइज्ड बैंक है इस मामले मे उन्होंने बिलकुल कोआपरेट नही किया। इतना मेरा तजुर्बा है।

श्री रणबीर सिंह : यह भी हो सकता है, लेकिन एक बात सही है कि जितने नेशनलाइज्ड बैंकों का संबंध है, मैं ने जिस की तरफ इशारा किया था टी० एन० सिंह जी को, जब कि वह मुख्य मंत्री थे कि आप सरकार की तरफ से गारंटी दें कि जो कर्ज किसान उठायेंगे, वह अगर अदा नही कर सकेंगे तो हमारी सरकार उस की जिम्मेदार है, वह गारंटी अभी तक नही दी गयी और आज तक उतना कर्ज नही मिला। इस लिए बहाना ही कह दीजिए लेकिन वह हुआ।

श्री उपसभाध्यक्ष (**श्री योगेन्द्र शर्मा**) : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रणबीर सिंह तो मै आखिर में यह निवेदन करता हूं कि किन्ही भाइयों को रूस का बुखार है, किन्ही को मारुति का बुखार है और किन्हीं को बंसीलाल का बुखार हो गया है इस से कोई तरक्की नही हो सकती। हमारे देश की तरक्की इस बात से हो सकती है कि मारुति की जो बातें करते है वे जा कर देखें कि संजय गांधी ने कितने थोड़े समय में कितना काम किया है, वह जा कर देखें कि बंसीलाल ने थोड़े से चार साल के अरसे में हरियाणा प्रदेश में कितना काम किया है। अगर वे वहां जा कर देखेंगे तो कुछ सीखेंगे।

श्री उपसभाध्यक्ष (**श्री योगेन्द्र शर्मा**) : अब आप समाप्त करिए।

श्री रणबीर सिंह : मारुति बहुत दूर नही है। अब जा कर देखें तो पता लग सकता है।

श्री महावीर त्यागी : आप के मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि मारुति के सिलसिले में इन्दिरा जी के लड़के ने 85 लाख रुपया कंसल्टेंसी की फीस का वसूल किया है। इस को करने की वजह से वह वहां से हटा कर दूसरी जगह . . .

(Interruption)

श्री रणबीर सिंह . आप की बात मैं समझा नहीं, लेकिन मै एक बात जानता हूं कि मारुति को हरियाणा सरकार ने कोई रियायत नही दी। मारुति की वजह से हरियाणा सरकार को फायदा हुआ *(Interruption)* जरा सुनिये। जिन किसानों की जमीन वह 1500 रुपये एकड़ में ले रहे थे छिपे हाथों से, उस जमीन की कीमत साढे ग्यारह हजार रुपये एकड़ तक उस को मिली है। तो इस प्रकार उन्होंने किसानो की सेवा की है। उन्होंने हरियाणा के लोगों को काम देने की व्यवस्था की है। आप को जो जलन है, जो आप को मिला है उस का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हरियाणा तो तरक्की करेगा, मारुति

तरक्की, करेगी यह आप को पसंद आये या न आये और उस से देश की तरक्की होगी। देश की तरक्की मे संजय गांधी हाथ बंटा रहा है और बटायेगा उन की माता जी हमारे देश की इज्जत बढ़ा रही हैं। यह आप की पसंद नहीं। आप कहते है कि वह देश की इज्जत घटा रही है। लेकिन कहने मे इज्जत घटती नही। दुनिया जानती है कि आज हिन्दुस्तान का नाम कितना ऊंचा गया है, इन्दिरा गांधी जब से प्रधान मंत्री बनी हैं हमारे देश की कितनी तरक्की हुई, हमारे देश की कितनी
5 P.M. शोभा बढ़ी है, यह दुनिया जानती है।

आप, यादव साहब, कितना ही दिल भर कर कोसे उससे कोई फर्क नही पड़ता।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI YOGENDRA SHARMA): Dr. Kurian.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: आज अब खत्म कीजिये, कब इसको लीजियेगा, पांच बज गये है।

श्री ओम मेहता: इसको आज खत्म करना है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: कल तो कोई एजेंडा है नही।

श्री ओम मेहता: कौन कहता है कि कोई एजेडा नहीं है। We have decied to sit up to six. I think we will finished it much earlier. much earlier.

श्री महावीर त्यागी. इतनी देर क्यों बैठाते है।

श्री ओम मेहता: आज इसको खत्म होने दीजिए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: कल छः बजे तक बिठाइयेगा आज छोड़ दीजिए।

श्री ओम मेहता: अभी आधा घटे में खत्म हो जायगा। इनके बोलने के बाद यह जवाब देंगी।

SHRI D. D. PURI (Haryana): Let us hear the hon. Member instead of wasting time. Let us get on with the job.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: कल छः बजे तक बैठा लीजियेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI YOGENDRA SHARMA): Order, order. Let us hear Dr. Kurian.

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala): Vice-Chairman, Sir, I rise to oppose the Appropriation (No. 3) Bill, 1973. Sir the Government has brought forward this Appropriation Bill not for a small sum of money. At a time when there is a very serious economic and financial crisis in the country this Appropriation Bill for additional sums is being brought forward by a Government which has been neglecting the question of economy in Government expenditure. Public expenditure has been mounting cheerfully without any control and we have now reached a stage where the Central Government, the Finance Ministry and the Planning Commission particularly are talking about pruning the Fifth Five Year Plan. There is brave talk by the Planning Minister of saving at least the core sector of the Plan. Despite all this we find that substantial expenditure is being incurred by Government. I am not now criticising all expenditure for which money has been sought through this Appropriation Bill but I am making a general statement that additional sums are being sought through Appropriation Bills from Parliament at a time when the Central Government itself is pursuing their age-old policy of cheerful expansion of even non-developmental, non-essential public expenditure. Sir, despite the serious crisis not only in the Indian economy but also in the international monetary sphere which affects our resources position, our foreign trade, our foreign exchange position, the Government of India is following an ostrich-like policy and their motto is, see no evil, hear no evil and speak no evil. But what is the reality? They have this motto of not speaking, not hearing or not seeing the evil of the economic crisis but what is

[Dr. K. Mathew Kurian]

really happening is that the planning process has been completely scuttled by the economic crisis. If anyone seriously talks about the Fifth Five Year Plan today I think he is living in a fool's paradise. The Fifth Five Year Plan has already been eroded. There is a *de facto* Plan holiday whether the Planning Minister says so or not. The Planning Minister may be shouting from the house top but there is a *de facto* Plan holiday. Prof. Gadgil who was the Deputy Chairman of the Planning Commission, a noted economist of this country, was honest enough to accept that the original Fourth Plan draft had no meaning and therefore he advised the declaration of a Plan holiday. That was an honest acceptance of a reality that there was a Plan holiday and the planning process was in a serious crisis. Today on the contrary the politician in Mr. D. P. Dhar is telling us that there is still hope for maintaining the Fifth Plan but the reality is that we have as serious or even a more serious crisis than the crisis we had in the year 1966 in the beginning of the original Fourth Five Year Plan when Prof. Gadgil honestly accepted the reality. Sir, today the reality is that there is a serious economic and financial crisis which has completely eroded the Fifth Plan. The talk now is to save the core sector. The Planning Commission's decision to scale down physical targets in the 1973-74 Plan should be discussed, along with the discussion on the Appropriation Bill. How can we discuss the Appropriation (No. 3) Bill, 1973 completely devoid of what is happening to this year's Plan and this year's budgetary allocations? The Annual Plan for 1973-74 with a total outlay of Rs. 4,364 crores has a Central sector outlay of Rs. 2,294 crores. It is being pruned at least to the extent of ten per cent in terms of financial targets. If I understand correctly, according to paper reports, the pruning will be of the order of ten per cent. In reality in terms of physical targets, it will be pruned much more, not only ten per cent, but much more. Therefore, the real planning process has come to such a stage. It is a tragedy which has occurred in the history of Indian planning. What is the contribution of the Finance Ministry in this exercise of economy? In the name of economy, the real core sector and I would say core sector not in terms of heavy industries but essential sectors are being cut down by the Finance Ministry. I would like to refer, for instance, to the statement which appeared in the Indian Express of August 20, only the other day, under the title 'economy' drive likely to hit job schemes'. The Centre's ambitious scheme to provide half a million jobs to the unemployed during the current year is likely to be one of the major casualties of the Cabinet's recent drive for economy. The scheme is to be slowed down. In the name of economy they cut down that expenditure which really helps the common people. We have all our criticisms . . .

SHRI MAHAVIR TYAGI: It is a hoax. They cannot effect an economy of even Rs. [illegible] crores.

DR. K. MATHEW KURIAN. I am coming to that. We are aware that the so-called paper schemes for the unemployed and the crash programmes are a fraud. We understand that. But at least we thought that even when this fraud is being played on the people, some of the expenditure in the truly useful sectors would trickle down to some people. Even that is being denied. My point is not that the scheme is a great scheme, but even the little benefits that would have trickled down to the ordinary people are being nullified in the name of economy. On the contrary, the Government of India allows all kinds of expenditure, for example, Rs 9 lakhs for the Delhi High Court for decorating it with marbles. All kinds of expenditure I can narrate. Some examples I can give of unplanned expenditure on non-essential items, but essential items which are only on paper are being nullified.

Another thing is this. The State Governments which have been trying to implement at least partially some of the essential schemes like irrigation and power and so on have, at the end of the year, found that their expenditure would be more than what was originally planned. In the Hindustan Times of August 19, there is a statement. It says that the States are likely to exceed the Fourth Plan outlays. Most of the items on which there is higher expenditure are in sectors like agriculture, irrigation and power, large and medium industries transport and communications, water supply, housing and welfare of the Backward Classes. It is a fact that at the

State level there is need for larger outlays, but the States will not get resources. The Central Government continue with their cheerful expansion of public expenditure and they cut down essential sectors where employment could be generated. What is now really happening is that, according to my knowledge, the Planning Commission has fallen back on the old practice of suggesting a mechanical cut in financial allocations in areas like education, particularly primary education, adult literacy, health and social services in general. This is the bureaucratic way of cutting down mechanically across the board in the name of economy. I can give you more examples. In the Andaman Islands certain public works were started by the Central Government employing hundred of workers. While employees have been brought from the mainland to the Andamans and they have started the construction, midway they reduced the allocation by Rs. 35 lakhs. Eight hundred workers brought from the mainland to the Andamans have been thrown out of jobs. There has been a strike, there has been a serious labour situation. And I have been meeting the Prime Minister and the Minister of State in the Ministry of Finance and requesting them that something should be done. Till today nothing worthwhile has been done. Some of the employees have been forced to take gratuity and leave because they had no choice. But the fact is that essential construction works even in the far away neglected Island of Andaman are being cut in the name of pruning and saving the core sector.

What has happened to the much-advertised promise of growth with social justice? Government spokesmen tell us that they have a new innovation in development planning that economic growth will be married to social justice. Today they have forgotten all about social justice. In the name of somehow hitting the figure of economic growth, in the name of percentage rate of growth, they are prepared to scuttle all schemes for social justice. Sir, even on questions like controlling the concentration of economic power in a few hands, of controlling the monopolies, and of having a more equitable distribution of wealth and income, they have now exhibited a discreet silence. Why are they silent about such crucial issues of economic policy. The loud noises about saving the core sector cannot completely nullify the fact that some of the very important linkages between economic growth and social justice are being neglected. You cannot have a high rate of growth unless you tackle the question of ownership of property, particularly big property. And it is precisely on this point of linkages between the core sector and schemes for social justice and the minimum needs programme that the Government has shown complete callousness in their policy. The minimum needs programme which was claimed to be the greatest innovation has been axed and sabotaged by the very protagonists of this scheme. Development planning has hit the rocks. There is undecided, undeclared Plan holiday. Let us accept the reality that there is a *de facto* Plan holiday. Those who have been vociferous in their denunciation about the three Plan holiday years are now sucking their thumbs and they have no solution to the problem of economic crisis posed by higher prices, inflation poverty and unemployment. I would even suggest that the Resources Working Group set up by the Planning Commission under the chairmanship of Prof. Chakravarti should be wound up, or maintained as a permanent working group. After all, this resource crisis is likely to stay.

Sir, the Appropriation Bill wants more money from this House on items like Foreign Trade, Currency and Coinage, Labour and Employment and so on. I would like to restrict myself to two or three points. Let us take the case of the Foreign Trade Ministry. I have no time to go into the details, that is not possible, today is not the occasion. But let me take the concrete case of the Coir Board. The Coir Board has now been shifted from the Foreign Trade Ministry to the Ministry of Industrial Development. It is a fact that during the last one year the Coir Board has never met—the Coir Board was not constituted for several months in the past—though under the Coir Board Act the Board is supposed to meet every three months. This is a very obvious neglect. All the representatives of labour from the CITU, the INTUC and the AITUC had been represented. The CITU was there on the Board during the last several years but that has now been eliminated. That means a deliberate policy of

[Dr. K. Mathew Kurian.]

eliminating genuine trade union representatives, representative of a major trade union.

Now, take the question of the Labour and Employment Ministry. I would like to give three instances of serious labour problems and irregularities with reference to the attitude towards labour which have been brought to the notice of the Government. Even today they have not moved an inch in the matter. Take the case of the I.I.T, Madras. Sir, in the Eleventh meeting of the Council of the Institutes of Technology held under the chairmanship of the Union Education Minister it was decided that appropriate Unions and Associations of the employees might be recognised for forming a suitable consultative machinery at the various I.I.Ts. But even today the Association of the I.I.T. Madras has not been recognised. Not only that, employees who are in charge of the maintenance of the Institute campus, in the residential quarters, hostel, laboratory etc. where the work is of a permanent nature are still classified as workcharge employees. The real benefit has been nullified to them. They have been denied the real benefit by calling them workcharge employees. The I.I.T. employees had submitted their memorandum and requested the Union Government to intervene in the situation so that a serious labour situation is avoided. I understand that because of the unwillingness of the Central Government to intervene in this case the employees are going on a very big march to the Raj Bhavan on the 25th of this month. Before the situation gets out of control, I would request the hon'ble Minister to inform the concerned Ministry that some action should be taken so that these problems can be avoided.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI YOGENDRA SHARMA): Conclude, please.

DR. K. MATHEW KURIAN: I am concluding. In conclusion I would like to say what I brought to the notice of the Government earlier, namely, the labour situation in the Bharat Scouts and Guides, the National Book Trust in Delhi.

The Gandhi Peace Foundation has hit the headline in the papers. This is what the National Herald of the 21st August has to say:—

> "Mr. N. Damodaran Nair, a freedom fighter, dedicated to the cause of 'establishment of the poor man's raj in India,' has decided to undertake a 25-day penance fast from Janamashtmi (August 21) in front of the Gandhi Peace Foundation office in Rouse Avenue.
>
> The purpose of the penance is to atone for the various acts of omission and commission on the part of the institution, Gandhian leaders who have joined hands with monopoly business houses and other reactionary forces, local and foreign in a bid to defeat the onward march of the progressive forces in the country."

When the Minister brings an Appropriation Bill asking for more money I would like her at least to look into some of these problems which have been umpteen number of times brought before the notice of the House.

SHRI DEBANANDA AMAT (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sirs, I thank you for giving me some minutes to express my views. Sir, we have completed 26 years of independence. During this period we have spent huge sums amounting to Rs. 49,091 crores in the name of the First, Second, Third and the Fourth Plan. It is estimated that during the Fifth Five Year Plan we are going to spend a heavy sum to the tune of Rs. 51,166 crores. But during these years we have celebrated our Silver Jubilee and we have coined catchy slogans like *Aaram Haram Hai, Garibi Hatao and* Green Revolution. But instead of the Green Revolution has come the Red Revolution.

Sir, I am very grateful to the economists of India who have suggested an 11-point programme for checking price rise. While suggesting that they have given a suggestion that our President, Mr. V. V. Giri, and the Prime Minister, Mrs. Gandhi should move to a modest flat. This is quite a good suggestion and would be a sign of and good symbol of gesture also. I am sorry while everybody, poor as well as the higher classes, has been asked to make sacrifices to pull the nation out of this economic morass they are going to

[Shri Debananda Amat.]

air-condition their offices. But what are they doing in Orissa? Sir, two-thirds of the people in Orissa consist of the Scheduled Castes and the Scheduled Classes. They form the hard core of the backward classes of this country. They are always ill-fed, ill-clad and illiterate. What is the Government doing for them? In every Adivasi village, they have started a new liquor shop. I met the Governor. I told him, "They are having a hand-to-mouth existence. There should not be any liquor shop in the Adivasi areas." But the Governor told me, "No, you go and persuade them not to drink." But persuasion will not help. It is a question of psychology—"out of sight, out of mind". If you start a liquor shop in any place, those who are habituated to it will drink again. It should be out of sight; then it will go out of their mind. I told him, "But doing this, you are robbing Peter to pay Paul." Another thing is, our Government, in the name of help, has given to the tune of Rs. 148 crores to Pakistan. Even to Iran and Iraq this country has given Rs. 13 crores. But they could not give Rs. 60,000 for this purpose. They can abolish land revenue, but they could not do without this Rs. 50,000 or Rs. 60,000. They want to extract it from the pockets of the Adivasis who can hardly make both ends meet.

Secondly, they started a lead smelting shop in Sargupalli in my district only to provide employment in our district where the prices are rising, where unemployment is galloping and corruption is mounting. Only to meet these things, they started a new lead smelting plant. But now we hear that this plant is going to be abolished or shifted somewhere. Thirdly, due to non-availability of wagons, the MMTC is not able to move manganese to other places; thereby, we are losing foreign exchange and, at the same time, the Railways is also losing freight. So, I oppose this Appropriation Bill.

उपसभाध्यक्ष (श्री योगेन्द्र शर्मा) : मंत्री जी आज जवाब देंगी या कल देंगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जैसा आप चाहें ।

SHRI NAWAL KISHORE : आप ऐसा कर दीजिए कि now the debate is closed and the Minister will reply tomorrow.

THE VICE CHAIRMAN SHRI YOGENDRA SHARMA): मंत्री महोदया कल जवाब देंगी । The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 23rd August, 1973.

MGIPCBE—S4—8 RSS/ND/73—6-12-73—595.